उत्तर प्रदेश

विशिष्ट करेंट अफेयर्स

अप्रैल 2023

बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भाटा (बैंगन) और चंदौली का आदमचीनी चावल को मिला जीआई टैग

• उत्तर प्रदेश के बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भाटा (बैंगन) और चंदौली का आदमचीनी चावल के साथ अन्य 7 उत्पादों को जीआई सर्टिफिकेट मिला है।

• गौरतलब है कि जीआई टैग यानि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक प्रकार का लेबल होता है, जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी विशेषता या फिर नाम खास तौर से प्रकृति और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है।

• धार्मिक और पर्यटन नगरी काशी जीआई हब के रूप में उभरी है। यहाँ के खास बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, रामनगर के भाटा (सफेद बड़ा गोल बैंगन) और आदमचीनी चावल (ज़िला चंदौली) को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (Geographical Indications) एवं बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) का तमगा मिला है।

• जीआई विशेषज्ञ ने बताया कि नाबार्ड एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रदेश के 11 उत्पादों को इस वर्ष जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिसमें 7 उत्पाद ओडीओपी (one district one product) में भी शामिल है और 4 कृषि एवं उद्यान से संबंधित उत्पाद काशी क्षेत्र से है। इनकी कुल संख्या अब 45 हो गई है।

'अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना'

• उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की 'अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना' को मंजूरी दी गई। इस योजना पर 400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

• 'अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना'के तहत सरकार ने प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल पर फ्लैट रेट की सुविधा दी है। शहरों में पाँच किलोवाट कनेक्शन वाले पावरलूम कनेक्शन धारकों को आधे हार्स पावर पर 400 और एक हार्स पावर पर 800 रुपए देना होगा। गाँवों में यह क्रमशः 300 और 600 रुपए होगा।

• इस योजना का लाभ एक अप्रैल 2023 से दिया जाएगा। वहीं, हथकरघा पर 80 और पावरलूम लगाने पर 60 फीसदी तक अनुदान मिलेगा।

• पाँच किलोवाट अधिक भार वाले पावरलूम कनेक्शन-धारकों को 700 रुपए प्रति हार्स पावर, अधिकतम 9100 रुपए हर माह अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान को बिल में कम कर दिया जाएगा।

• वहीं, सूक्ष्म, लघु उद्यम निर्यात प्रोत्साहन तथा खादी ग्रामोद्योग हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। बेरोज़गार को रोज़गार से जोड़ने के लिये 'झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना' शुरू की गई है। बुनकरों को हथकरघा के दो अनुमानित मूल्यों पर 50 हज़ार रुपए और 80 हज़ार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

• निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को बोनस नहीं देने वाले नियोक्ता को अब जेल नहीं होगी। इस प्रस्ताव के तहत बोनस संदाय अधिनियम-1965 में संशोधन को मंजूरी देते हुए छह माह तक सजा के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।

• नए प्रावधान के तहत जुर्माने की राशि जो एक हज़ार रुपए थी, उसे बढ़ाकर दस हजार रुपए कर दिया गया है। इसमें भी शमन की व्यवस्था दी गई है।

• विदित है कि अब तक कर्मचारियों को बोनस नहीं देने पर नियोक्ता को छह माह की सजा या 1000 रुपए जुर्माना अथवा सजा व जुर्माना दोनों लगाए जाने का प्रावधान था।

मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित

• 5 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार (द्वितीय संस्करण) में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत (Posthumously) पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनकी तरफ से यह सम्मान उनके बेटे अखिलेश यादव ने ग्रहण किया।

• विदित है कि मुलायम सिंह यादव का लंबी बीमारी के बाद पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था। मुलायम सिंह उस वक्त मैनपुरी सीट से लोकसभा सांसद थे। यह सीट रिक्त होने के बाद कराए गए चुनाव में उनकी बहू डिंपल यादव निर्वाचित होकर लोकसभा पहुँची हैं।

• उल्लेखनीय है कि मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा। वह उत्तर प्रदेश के तीन बार सीएम और नौ बार विधायक रहे। अपने राजनीतिक जीवन में उन्हें रक्षा मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी भी मिली थी।

• 2023 में मुलायम सिंह यादव के अलावा कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा, मणिपुर में बीजेपी के अध्यक्ष थौनाओजम चौबा सिंह और त्रिपुरा के दिवंगत नेता नरेंद्र चंद्र देबबर्मा को भी पद्म विभूषण दिया गया है।

• विदित है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को पद्म पुस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा हुई थी। उनमें से एक नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम दिवंगत मुलायम सिंह यादव का भी था।

• गौरतलब है कि पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार की ओर से दिये जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। इस साल कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री सम्मान शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा

• योगी सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग की बैठक में तय हुआ है कि यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। मदरसे समेत सभी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति यही आयोग करेगा। यही नहीं, टीईटी की परीक्षा भी यही आयोग करवाएगा।

• अभी प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के चयन के लिए अलग-अलग प्राधिकारी, बोर्ड और आयोग गठित हैं। अभी तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए शिक्षकों की भर्ती हो रही थी। लेकिन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ही शिक्षकों की भर्ती होगी।

• नए आयोग में यूनिवर्सिटी के कुलपति जैसे पद या भारतीय प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव रखने वाले को अध्यक्ष बनाया जाएगा। आयोग के सदस्यों में रिटायर्ड सीनियर जज और अनुभवी शिक्षाविद की नियुक्ति की जाएगी। आयोग में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और अल्पसंख्यक वर्ग का भी प्रतिनिधित्व रखा जाएगा।

• राजकीय महाविद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, संस्कृत महाविद्यालय और अल्पसंख्यक महाविद्यालय, एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज और अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों में एकीकृत शिक्षा चयन आयोग के जरिए ही भर्ती होगी। आयोग को इस बात का ध्यान रखना होगा कि TET भी समय पर हो।

• समय पर भर्ती कराने, मानव संसाधन का बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुशासन में शिक्षा सेवा चयन आयोग की भूमिका अहम होगी। शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा, साक्षात्कार आदि की जिम्मेदारी नियुक्ति प्राधिकारी करेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया

• उत्तर प्रदेश सरकार वार्षिक वृक्षारोपण अभियान के तहत इस साल 35 करोड़ पौधे लगाएगी। लखनऊ में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये पौधे राज्य के सभी जिलों में एक ही दिन में लगाए जाएंगे।

• उन्होंने कहा कि वन संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। श्री योगी ने कहा कि अब उत्तरप्रदेश के अधिकांश शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। सरकार ने डीजल और पेट्रोल वाहनों के लिए स्क्रैपिंग नीति लागू की है और धीरे-धीरे ऐसे वाहनों को सड़कों से हटाकर इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है।

• इस अवसर पर केंद्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रीभूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों को साकार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारत का विकास इंजन बन रहा है।

• उन्होंने बताया कि उत्तरप्रदेश आज सबसे ज्यादा एथेनॉल का उत्पादन कर रहा है। राज्य में आयोजित दो दिवसीय जलवायु सम्मेलन 2023 पर्यावरण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।

• श्री यादव ने कहा कि आज भारत वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और 2015 के पेरिस समझौते पर इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का प्रभाव है।

• उन्होंने कहा कि आज भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विश्व में सबसे कम है और देश ने अपने नागरिकों की जीवन शैली से दुनिया को दिखा दिया है कि जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार के साथ समाज को भी काम करना होगा।

• दो दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 में जलवायु परिवर्तन, वन और वन्य जीव संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूँ खरीद नीति को मंजूरी दी

• उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गेहूँ खरीद नीति को हरी झंडी दे दी है। यह मंजूरी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये दी गई है। इसके तहत 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ की खरीद होगी।

• खाद्य विभाग, मंडी परिषद, पीसीएफ, यूपी कोऑपरेटिव यूनियन, उपभोक्ता सहकारी संघ, राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम और भारतीय खाद्य निगम के 6 हज़ार केंद्रों के माध्यम से यह खरीद होगी।

• कुल 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को गेहूँ की बिक्री के लिये खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

• विदित है कि प्रदेश में एक अप्रैल से गेहूँ की खरीद प्रारंभ कर दी गई है। हालाँकि, सरकारी क्रय केंद्रों पर अभी गेहूँ की आमद काफी कम है।

• चावल पर काम कर रहे चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी को अब और अतिरिक्त भूमि दी जाएगी। इसके लिये कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

• अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी चावल पर अच्छा काम कर रहा है। काला नमक चावल पर किया गया अनुसंधान और इसका कार्य प्रशंसनीय रहा। ऐसे में इसे और विकसित करने का प्रस्ताव लाया गया है। इस संस्थान को अब 0.97 हेक्टेयर ज़मीन और दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के दो पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023

• राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायतों को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की दो ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया।

• सिद्धार्थनगर ज़िले के भँवापुर ब्लाक की ग्राम पंचायत हंसुदी औसानपुर को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया।

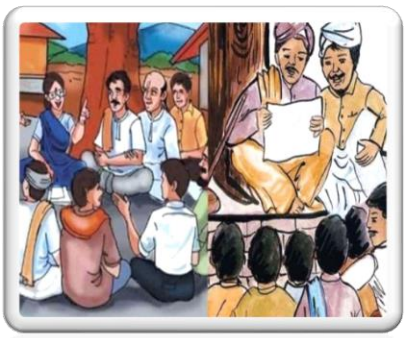

• ग्राम पंचायत हंसुदी औसानपुर को यह पुरस्कार 'बाल हितैषी पंचायत'की श्रेणी में प्रदान किया गया है।

वहीं मुरादाबाद ज़िले के दिलारी ब्लाक के ग्राम पंचायत मिलक अमावती को सभी 9 एलएसडीजी विषयों और हरित पहल से संबंधित

विशेष श्रेणियों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिये नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (एनडीएसपीएसवीपी) प्रदान किया गया।

• निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों में चुनी गईं पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किये गए–

1. व्यक्तिगत एलएसडीजी विषय वस्तुओं के तहत प्रदर्शन के लिये दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी)

2. सभी 9 एलएसडीजी विषयों और हरित पहल से संबंधित विशेष श्रेणियों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिये नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (एनडीएसपीएसवीपी)

3. ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार

4. कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार।

गोरखपुर में बनेगा प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय

• मंडलायुक्त गोरखपुर रवि कुमार एनजी ने बताया कि सीएसआर के तहत गोरखपुर में प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय बनेगा। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सारी सुविधाएँ उपलब्ध होगी।

• सीएसआर के तहत करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर ज़िले में प्रस्तावित महिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा।

• इस विश्वविद्यालय में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था होगी। बालिकाओं के उत्थान के लिये जरूरी सुविधाओं के आकलन हेतु कंसल्टेंसी फर्म को जिम्मेदारी दी गई है।

• गोरखपुर में प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय रियल एस्टेट कंपनी शोभा डेवलपर की ओर से लिया गया है, जिसको लेकर कंपनी के अधिकारियों ने गोरखपुर का दौरा भी किया था।

• इस महिला विश्वविद्यालय के लिये ज़िला प्रशासन द्वारा 100 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी और इसका संचालन भी कंपनी की ओर से किया जाएगा।

• विदित है कि गोरखपुर में पहले से चार विश्वविद्यालय संचालित हैं, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय शामिल हैं। महिला विश्वविद्यालय बन जाने से गोरखपुर में पाँच विश्वविद्यालय हो जाएंगे।

• गोरखपुर में महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य कंपनी का फोकस महिलाओं के उत्थान पर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिये सुविधाओं की काफी ज़रूरत है। पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने में यह विश्वविद्यालय काफी कारगर साबित होगा।

वाराणसी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

• उत्तर प्रदेश के वाराणसी के राजातालाब तहसील के गंजारी में 32 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जिसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

• वाराणसी में बनने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पीपीपी मॉडल पर संचालित होगा। इसका निर्माण भी इसी तर्ज पर कराया जाएगा। ईपीसी मॉडल पर निर्माण के लिये यूपीसीए की ओर से निर्माण कंपनी के चयन हेतु टेंडर भी जारी कर दिया गया है।

• ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड डिजाइन (इंजीनियरिंग, सामानों की खरीद और डिजाइन) मोड पर काम के लिये कंपनी का चयन किया जाएगा।

• ऑनलाइन जारी टेंडर में कंपनियाँ यूपीसीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन बोली लगा सकती हैं। बोली लगाने वाली कंपनियों को सुरक्षा राशि के तौर पर पाँच करोड़ रुपए जमा करने होंगे।

• टेंडर की शर्त के अनुसार जिस भी कंपनी का चयन किया जाएगा, उसे 30 महीने यानी ढाई साल में स्टेडियम का निर्माण पूरा कर यूपीसीए को हैंडओवर करना होगा।

• इस स्टेडियम की क्षमता 30 हज़ार दर्शकों की होगी। स्टेडियम निर्माण में करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होगा।

• विदित है कि हाल ही में बीसीसीआई सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के साथ विशेषज्ञों ने प्रस्तावित ज़मीन का निरीक्षण भी किया था।

केरल में वाटर मेट्रो की तर्ज पर काशी में दौड़ेगी वाटर टैक्सी

• भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन संजय बंधोपाध्याय ने बताया कि केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नमो घाट (सबसे उत्तर) से अस्सी घाट (सबसे दक्षिण) के बीच वाटर टैक्सी भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और पर्यटन विभाग के सहयोग से चलाई जाएगी।

• यह टैक्सी वाराणसी के सभी 80 घाटों के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चलेगी। बीच में इसके लिये चार स्टेशन बनाए जाएंगे। सभी घाटों पर जलमार्ग प्राधिकरण फ्लोटिंग जेटी उपलब्ध कराएगा। इससे लोगों का टैक्सी में चढ़ना और उतरना आसान हो जाएगा।

• इस वाटर टैक्सी का इस्तेमाल न सिर्फ परिवहन के लिये किया जा सकेगा बल्कि लोग बनारस के खूबसूरत घाटों का नज़ारा भी इससे ले सकेंगे।

• ज्ञातव्य है कि अभी बनारस में क्रूज और कार्गो का संचालन हो रहा है। इसका इस्तेमाल केवल पर्यटक ही करते हैं। लेकिन वाटर टैक्सी का इस्तेमाल बनारस के लोग सड़क पर जाम से छुटकारे के लिये भी कर सकेंगे।

• उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो का शुभारंभ किया।

उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन और विश्व बैंक के बीच हुआ समझौता

• लखनऊ में आयोजित गन्ना किसानों के वृहद हित लाभ के लिये कार्यशाला में प्रदेश के शुगर मिल्स एसोसिएशन और विश्व बैंक के बीच 'सूक्ष्म सिंचाई' पर एक सामान्य दृष्टि और प्राथमिकताओं के अनुरूप दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने के लिये समझौता हुआ है।

• विश्व बैंक की ओर से अजित राधाकृष्णन और उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन की ओर से महासचिव दीपक गुप्तारा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये।

• 2030 डब्ल्यूआरजी ने अपने पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश परियोजना के अंतर्गत 'ड्रिप इरिगेशन' के बारे में एक प्रस्तुति दी। कार्यशाला में मैसर्स गुजरात ग्रीन रेवोलुशन कंपनी (जीजीआरसी), अहमदाबाद ने भी उत्तर प्रदेश सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिये विकसित किये जा रहे 'न्यू सिंगल विंडो डिलीवरी मॉडल' को पेश किया और गुजरात के गन्ना किसानों के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा किया। किये गए कार्यों की समीक्षा

से ज्ञात हुआ कि गुजरात राज्य में गन्ना किसान लगभग 30 प्रतिशत पानी की बचत करने में सफल रहे।

• विश्व बैंक अपने जल संसाधन समूह और यूपीएसएमए 'यूपी प्रगति एग्री वाटर एक्सेलरेटर' (यूपी प्रगति कृषि जल त्वरक कार्यक्रम) को लागू करने के लिये साथ मिलकर काम कर रहा है।

• यह परियोजना राज्य के गन्ना किसानों के समग्र लाभ के लिये स्थायी 'सूक्ष्म सिंचाई मॉडल' विकसित करने के लिये दो संगठनों की सामर्थ्य का समन्वय करती है। कार्यक्रम वर्तमान प्राथमिकता मानदंड के आधार पर राज्य के 38 से अधिक जनपदों में वृहद स्तर पर सहायता कार्यक्रम चलाने का इच्छुक है। इससे गन्ना किसानों की उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आने का अनुमान है।

• परियोजना मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगी-

1. गन्ने की खेती में जल कुशल आचरण को बढ़ावा देना।

2. गन्ने की खेती के मशीनीकरण को बढ़ावा देना।

3. लो कार्बन एर्गोनोमिक संचालन को बढ़ावा देकर चीनी संवर्धन श्रृंखला को डी-कार्बोनाइज करना।

• विदित है कि उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन (यूपीएसएमए) उत्तर प्रदेश में निजी चीनी मिलों का एक प्रमुख संगठन है। यूपीएसएमए का मुख्य उद्देश्य सरकार की अनुकूल और विकासोन्मुख नीतियों के माध्यम से प्रदेश में निजी चीनी मिलों के कामकाज और हितों की रक्षा को सुनिश्चित करना है। यूपीएसएमए राज्य में गन्ना किसानों और उद्योग हित में 1938 से कार्यरत है।

• 2030 जल संसाधन समूह, विश्व बैंक समूह का एक सार्वजनिक, निजी, सिविल सोसाइटी मल्टी-डोनर ट्रस्ट फंड है। डब्ल्यूआरजी (WRG) सामूहिक निर्णय लेने और पानी से जुड़े सभी क्षेत्रों में मज़बूत सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले लीक से हटकर (आउट-ऑफ-द-बॉक्स) समाधानों को सह-डिजाइन करने में हितधारकों का समर्थन करता है।

उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा विद्यालयों से हटाए जाएंगे सभी पुरुष स्टाफ

• वर्तमान में प्रदेशभर में संचालित 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत सभी पुरुष स्टाफ को हटाया जाएगा।

• उत्तर प्रदेश स्कूली शिक्षा महानिदेशक और समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर पुरुष कार्मिक का नवीनीकरण न करने का आदेश दिया है।

• उत्तर प्रदेश स्कूली शिक्षा का यह कदम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में आवासीय सुविधा के साथ कक्षा छह से आठ तक की शिक्षा ग्रहण कर रहीं छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत लिया गया है।

• ज्ञातव्य है कि शिक्षा मंत्रालय में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव ने 12 अक्टूबर, 2022 को पत्र लिखकर कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में सभी पदों पर महिला कार्मिकों की ही नियुक्ति किए जाने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में 2023-24 शैक्षणिक सत्र में पुरुष स्टाफ का नवीनीकरण न करने और रिक्त हो रहे पदों पर सिर्फ महिलाओं को नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

• कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में वार्डेन से लेकर चौकीदार तक सभी कार्मिकों को संविदा पर रखा जाता है। राज्य में कानपुर नगर और औरैया ज़िलों को छोड़कर सभी जिलों के प्रत्येक विकासखंड में एक-एक कस्तूरबा विद्यालय संचालित है।

• कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में केवल महिला कार्मिकों के नवीनीकरण के आदेश से एक हज़ार से अधिक पुरुष स्टाफ के प्रभावित होने का अंदेशा है।

• प्रदेशभर के 746 विद्यालयों में अधिकांश लेखाकार और चौकीदार पुरुष हैं। कुछ जगहों पर शिक्षक भी पुरुष हैं। ऐसे में प्रत्येक स्कूल पर दो पुरुष कार्मिक का भी अनुमान लगा लें तो डेढ़ हज़ार के आसपास स्टाफ प्रभावित होगा।

वाराणसी से प्रयागराज के बीच क्रूज संचालन के लिये सर्वे पूर्ण

• भारतीय अंतर-देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निदेशक एल.के. रजक ने बताया कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत क्रूज सेवा के संचालन के लिये भारतीय अंतर-देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी-प्रयागराज के बीच सर्वे पूरा कर लिया है।

• एल.के. रजक ने बताया कि जुलाई में इसे शुरू करने की तैयारी है। ट्रायल सफल रहा तो इस रूट पर जलयान की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही मालवाहक जलयान के संचालन की भी योजना है।

• वाराणसी और प्रयागराज के बीच चलने वाला क्रूज सैलानियों को गंगा दर्शन के साथ ही पर्यटक स्थलों की भी सैर कराएगा।

• इस सर्वे में कई जगहों पर जल परिवहन की बाधाओं को चिह्नित किया गया है। इसके साथ ही चुनार, विंध्याचल, सीतामढ़ी सहित पर्यटन स्थलों पर जेटी का निर्माण भी कराया जाएगा। इस प्रयोग के सफल होने के बाद जलमार्ग प्राधिकरण क्रूज सेवाओं में बढ़ोतरी भी करेगा।

• धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रयागराज और वाराणसी के बीच के सभी पर्यटक स्थलों को जोड़ते हुए जलमार्ग प्राधिकरण नया रूट तैयार करने में जुटा है। सुबह से लेकर शाम तक पूरी होने वाली एक तरफ की यात्रा को पीपीपी मोड (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के जरिये संचालित करने की योजना है।

• इसके लिये कई निजी कंपनियों ने योजना में रुचि भी दिखाई है। इसमें निजी कंपनी के चयन के बाद किराया और अन्य सुविधाओं पर निर्णय लिया जाएगा। इसमें वाराणसी से चुनार, विंध्याचल, सीतामढ़ी और प्रयागराज में जेटी का निर्माण कर यहाँ ठहराव की व्यवस्था की जाएगी।

• इन स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिये जलमार्ग प्राधिकरण स्थानीय प्रशासन से अपनी कार्ययोजना साझा करेगा। दरअसल, पीएम गति शक्ति योजना के तहत वाराणसी प्रयागराज के बीच नए क्रूज संचालन के जरिये चुनार का किला, माँ विंध्यवासिनी धाम और सीता समाहित स्थल तक पहुँचने के लिये गंगा घाटों का विकास भी किया जाएगा।

• पीएम गति शक्ति योजना के तहत वाराणसी को जलमार्ग का नया केंद्र बनाया जा रहा है। रामनगर मल्टीमॉडल टर्मिनल को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना है। वाराणसी से हल्दिया तक मालवाहक जलयान का संचालन पहले से ही किया जा रहा है। गंगा विलास क्रूज के जरिये दुनिया के सबसे लंबे नदी मार्ग से वाराणसी का जुड़ाव किया गया है। प्रयागराज तक क्रूज संचालन के जरिये वाराणसी को केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है।

लखनऊ और हरदोई ज़िलों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल्स पार्क का शुभारंभ

• केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में राज्य के लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किया।

• लखनऊ में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में 'PM MITRA योजना'के अंतर्गत लखनऊ और हरदोई में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु MoU हस्ताक्षरित हुआ।

• पीएम मित्र पार्क लखनऊ को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास होगा। विशेष प्रयोजन वाहन (एस.पी.वी.)/मास्टर डेवलपर न केवल औद्योगिक पार्क का विकास करेगा बल्कि रियायत अवधि में इसका रखरखाव भी करेगा।

• पीएम मित्र पार्क लखनऊ का कुल क्षेत्रफल 1,000 एकड़ होगा, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है और इससे एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष और दो लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्राप्त होने की उम्मीद है।

• पीएम मित्र पार्क लखनऊ ज़िले के मलिहाबाद ब्लॉक के अटारी गाँव में विकसित किया जा रहा है, जो सड़क, रेल और हवाई संपर्क से देश के प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पार्क का निकटतम समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो कानपुर है, जो पार्क से 95 किलोमीटर की दूरी पर है।

• पीएम मित्र पार्क लखनऊ में एक इनक्यूबेशन केंद्र, सामान्य प्रसंस्करण गृह, एक सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्र और डिजाइन केंद्र और परीक्षण केंद्र एवं अन्य वस्त्र संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

• इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार सामान्य अवसंरचना का विकास करने के लिये पीएम मित्र पार्क लखनऊ को 500 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगी।

• पीएम मित्र पार्क लखनऊ कपड़ा उद्योग क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये मजबूती प्रदान करेगा।

• विदित है कि फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में एक सफल वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 33 लाख 50 हज़ार करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इसमें से 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव कपड़ा क्षेत्र के लिये है।

• भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय, पीएम मित्र पार्क लखनऊ में स्थापित होने वाली विनिर्माण इकाइयों को 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

• भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने पीएम मित्र पार्क लखनऊ में स्थापित होने वाली विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये 300 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है।

प्रदेश में बसेगी आईटी, मेडिसिटी, एजुकेशन सिटी और स्पोर्ट्स सिटी

• राज्य सरकार प्रदेश में बंगलुरु की तर्ज पर आईटी सिटी व महाराष्ट्र की तर्ज पर मेडिकल सिटी बसाने जा रही है। बेहतर शिक्षा हेतु एजुकेशन सिटी और स्पोर्ट्स सिटी भी बसाए जाएंगे।

• जानकारी के अनुसार इसकी जिम्मेदारी आवास विभाग को दी गई है। वह इसके लिये भवन विकास उपविधि में व्यवस्था करने के साथ ही नीति लाने जा रहा है। इस योजना से प्रदेश के 50 हज़ार युवाओं को रोज़गार मिलने की उम्मीद है।

• राज्य सरकार कि योजना है कि देश दुनियाँ की नामी-गिरानी दवा कंपनियों के लिये ऐसा स्थान विकसित किया जाए जहाँ पर सभी सुविधाएँ हों, इसके लिये महाराष्ट्र की तर्ज पर मेडिकल सिटी बसाने की योजना है। इसके लिये कम से कम 200 से 300 एकड़ ज़मीन की व्यवस्था की जाएगी।

• सभी प्रमुख शहरों को एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बड़े कालेज और विश्वविद्यालय खोलने के लिये आमंत्रित किया जाएगा।

• इसके साथ ही बंगलुरु की तर्ज पर आईटी सिटी बसाने का खाका खींचा जा रहा है। विदित है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लखनऊ में आईटी सिटी की स्थापना की गई थी, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक यह पर्याप्त नहीं है। इसीलिये राज्य राजधानी क्षेत्र में इसके लिये खास इंतजाम किये जाएंगे।

• मेडिकल सिटी और आईटी सिटी के सहारे हर साल 50 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। देश में अभी आईटी सेक्टर में सर्वाधिक नौकरियाँ बंगलुरु और पुणे में है।

• राज्य सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रदेश में ही अच्छी शिक्षा मिलने के साथ ही रोज़गार के संसाधन मिल सकें। इसीलिये आईटी सिटी खोलने की दिशा में काम शुरू किया जा रहा है। मेडिकल सिटी में इससे जुड़े क्षेत्र में रोज़गार के द्वार खुलेंगे।

• विदित है कि वर्ष 2016 में लखनऊ में आईटी सिटी का शुभारंभ किया जा चुका है। लखनऊ-सुलतानपुर रोड पर 100 एकड़ में आईटी सिटी की स्थापना की गई है। यहाँ एचसीएल काम कर रही है। आईटी सिटी के जरिये लगभग 5000 लोगों को रोज़गार मिला है।

• गौरतलब है कि देश का पहला मेडिकल सिटी महाराष्ट्र के इंद्रायणी में 300 एकड़ में बसाया जा रहा है। इसमें अस्पताल, अनुसंधान केंद्र, दवा फैक्ट्रियाँ, वेलनेस व फिजियोथेरेपी केंद्र आदि होते हैं।

चुनाव आयोग ने रालोद से छीना राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा

• भारत निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी करते हुए विधानसभा चुनाव में आठ सीटें जीतने वाली राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की पार्टी से उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। इस आदेश के बाद अब रालोद एक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बन गया है।

• आयोग के मुताबिक विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले दल को कुल वोटों का न्यूनतम छह प्रतिशत हासिल करने पर राज्य स्तर के दल की मान्यता दी जा सकती है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने आठ सीटों पर जीत हासिल की थी, हालाँकि उसे महज 2.85 प्रतिशत वोट ही हासिल हुआ था। इसी तरह वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में रालोद के हिस्से में कोई सीट नहीं आई थी और उसे महज 1.69 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे।

• वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गिरीश चौधरी हैं। इस पार्टी की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने की थी।

• विदित है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ गठबंधन किया था और 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से आठ सीटों पर विजय प्राप्त की थी।

• गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) से आंध्र प्रदेश में और राष्ट्रीय लोक दल (RLD) से उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस लिया है। वहीं रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को पश्चिम बंगाल में एक राज्य पार्टी के रूप में अमान्य किया गया है।

• साथ ही चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को नागालैंड में, टिपरा मोथा पार्टी को त्रिपुरा में और वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी को मेघालय में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता मिली है।

• दरअसल चुनाव आयोग ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के स्टेटस की समीक्षा करता है, जो सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 2019 से अब तक चुनाव आयोग ने 16 राजनीतिक दलों के स्टेटस को अपग्रेड किया है और 9 राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दलों के करंट स्टेटस को वापस लिया है।

मंगलायतन विश्वविद्यालय को मिला नैक ए प्लस ग्रेड

• मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद (नैक) ने ए प्लस (NAAC A+) ग्रेडिंग प्रदान की है।

• विदित है कि नैक की पाँच सदस्यीय टीम ने 22 से 24 फरवरी तक विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया था। टीम ने विश्वविद्यालय की अकादमिक एवं अनुसंधान गुणवत्ता के साथ प्रशासनिक व ढाँचागत व्यवस्था का भी मूल्यांकन किया था और विद्यार्थियों, पूर्व छात्रों एवं अभिभावकों के साथ ही स्टाफ के साथ बैठक कर चर्चा की थी एवं फीडबैक भी लिया था।

• विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीके दशोरा ने बताया कि अक्टूबर 2022 में सेल्फ एसेसमेंट रिपोर्ट (एसएसआर) नैक में सबमिट की गई थी।

• उल्लेखनीय है कि नैक मूल्यांकन किसी भी विश्वविद्यालय की गुणवत्ता जाँचने के लिये होता है। संस्थान द्वारा नैक ग्रेडिंग के लिये आवेदन करना होता है, आवेदन करने के बाद नैक की टीम संस्थान का निरीक्षण करती है। टीम शैक्षणिक सुविधाएँ, अनुसंधान, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि व्यवस्थाओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार करती है। इसी के आधार पर ग्रेड दिया जाता है।

• इसका काम देशभर के विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, निजी संस्थानों में गुणवत्ता को परखना और उनको रेटिंग देना है। नैक ग्रेडिंग से विद्यार्थियों को संस्थान का चयन करने में शिक्षा की व्यवस्था, अनुसंधान, बुनियादी ढाँचे के लिये बेहतर विकल्प की सुविधा मिलती है।